टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों को भूमि का आवंटन

1799. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए हरिद्वार में भूमि की पहचान की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देहरादून शहर के पास पुराने चाय बागानों की कई हजार एकड़ भूमि की बिक्री हेतु एक प्रस्ताव था, जो भूमि उपयोग को परिवर्तित किए बिना संभव नहीं था;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मसले को उच्च स्तर पर उठाया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि अधिकांश विस्थापित लोग उत्तरांचल में हरिद्वार को शामिल न किए जाने की स्थिति में वहां भूमि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार विस्थापित लोगों के हितार्थ इन मामलों के संबंध में क्या उपचारी योजनाएं बना रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (ग) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यान्वयन टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में वे शामिल होंगे जो कॉफर बांध के निर्माण से प्रभावित होंगे, दूसरे चरण में मुख्य टिहरी बांध द्वारा प्रभावित बचे हुए सभी परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। पहले चरण में पूर्णतः प्रभावित 5291 शहरी परिवार और 2064 ग्रामीण परिवार शामिल हैं। प्रथम चरण की पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है।

चरण-2 पुनर्वास कार्यक्रम में बचे हुए 2845 पूर्णतः प्रभावित ग्रामीण परिवार शामिल हैं, 435 परिवारों का पुनर्वास पहले ही किया जा चुका है। बचे हुए 2410 पूर्णतः प्रभावित ग्रामीण परिवारों के लिए कम से कम 5000 एकड़ की अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। 450 एकड़ के चाय बागान सहित 2550 एकड़ भूमि (1756 हरिद्वार जिले में और 794 एकड़ देहरादून जिले में) का अधिग्रहण हेतु निर्धारण किया गया है जिसका प्रस्ताव टी०एच०डी०सी० द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उच्चस्तरीय कृतिकबल ने निर्णय लिया है कि मुद्दों का निदान आयुक्त, गढ़वाल उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय भू-खोजी समिति के माध्यम से किया जाएगा। कृतिक बल के अध्यक्ष सचिव, विद्युत मंत्रालय हैं और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव शामिल हैं।

कमी वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विद्युत

1800. **श्री बरजिन्दर सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विविध क्षेत्रों ने बिजली का उत्पादन करने के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक क्षमता अधिष्ठापित की है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जहां उत्पादन क्षमता उनकी आवश्यकता से अधिक है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस अतिरिक्त बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम): (क) और (ख) हालांकि अधिष्ठापित क्षमता व्यस्तम-कालीन मांग से अधिक है, तथापि सभी क्षेत्रों को वर्ष 1998-99 के दौरान (नवम्बर, 1998 तक) व्यस्तम-कालीन कमी महसूस हुई है तथापि पूर्वी क्षेत्र में विद्युत अधिशेष है, किन्तु लाभ भोगी राज्यों की भुगतान संबंधी समर्थता और राज्य प्रणालियों में पारेषण एवं वितरण संबंधी बाधाओं से उपलब्धता सीमित है।

(ग) और (घ) 5 अन्तः क्षेत्रीय संयोजना अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के निर्यात करने संबंधी सुविधायें पहले ही से विद्यमान है, पड़ौसी क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विधमान अन्तःक्षेत्रीय पारेषण पर पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी दक्षिण और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को 650 मे०वा० तक बिजली का निर्यात शुरू कर दिया गया है अतिरिक्त अन्तःक्षेत्रीय संयोजन जैसे गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच) बोंगई गांव-मालदा 400 के०वी० डी/सी (पूर्वी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच), कोरबा बुद्धिपडार तृतीय सर्किट (पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच) निर्माणाधीन है जो कि मार्च, 1999 के अन्त तक क्षेत्र के बाहर 1100 मे०वा० बिजली के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराएगें। सासाराम में पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच एचवीडीसी बैक-टू-बैक

संयोजन के चालू होने के पश्चात मार्च, 2002 में नौवीं योजना के अन्त तक 1600 मे०वा० विद्युत का निर्यात संभव हो सकेगा।

Setting up of power projects by private sectors

1801. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of power projects set up by different private sector power companies in the country;

(b) their location, installed capacities and progress in power generation;

(c) whether several other power projects proposed to be set up in the private sector are pending for the clearance of Planning Commission, Central Electricity Authority and also for the clearance of the Ministry of Environment and Forests; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) As on date, 5 power projects in the private sector having an installed capacity of 1761 MW have been fully commissioned. Details are given below:

S.No.	Name of the Project	Capacity (MW)	State/District
1.	Baroda Combined Cycle Gas Turbine	167	Gujarat/Baroda
2.	Hazira Combined Cycle Gas Turbine	515	Gujarat/Surat
3.	Paguthan Combined Cycle Gas Turbine	655	Gujarat/Bharn
4.	Godavari Combined Cycle Gas Turbine	208	Andhra Pradesh/East Godavari
5.	Jegurupadu Combined Cycle Gas Turbine	216	Andhra Pradesh/East Godavari

(c) and (d) As on date the Detailed Project Reports (DPRs) for 62 proposals for setting up power projects in the private sector have been received in the Central Electricity Authority for accord of techno-economic clearance. Of these, 48 projects having an aggregate capacity of 22,631.7 MW and involving an estimated expenditure of Rs. 91,846.428 crores have already been accorded techno-economic clearance. The remaining 14 projects, having an aggregate capacity of 6782.9 MW, can be taken up for techno-economic appraisal only after the pending inputs/clearances are tied up by the project promoters. As per information available, none of these 14 projects are presently pending with the Ministry of Environment & Forests. Proposals for setting up power projects in the private sector are not required to be cleared by the Planning Commission.

Third Phase of Ennore Project

1802. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of POWER be pleasd to state:

(a) whether it is a fact that during a meeting held with the Chief Minister of Tamil Nadu recently, the Union Power Minister has announced the Commissioning of the third phase of Ennore Power Plant in Chennai;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government will invite the participation of private investors in this projects; and

(d) if so, the details thereof?